

स्टार्टअपस संग एमपी की मजबूत मौजूदगी

देश में बढ़ा स्टार्टअप का दबदबा, 52 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
भोपाल, 9 सितम्बर. देश में स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ रही है. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सरकार ने 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है, जो स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से किसी एक वर्ष में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की सर्वाधिक संख्या है.

31 मार्च 2026 तक देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.23 लाख को पार कर गई थी. इन स्टार्टअप से 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं.

निवेश और नौकरी के नए विकल्प- वित्त वर्ष 2025-26 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या



में वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 51.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इसी अवधि में प्रत्यक्ष रूप से सृजित नौकरियों में भी 36.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. स्टार्टअप अब देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं. मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है. 30 जून 2026 तक मध्य प्रदेश में 8,194 संस्थाओं को

डीपीआइआईटी की ओर से स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी जा चुकी थी. इस आंकड़े के साथ मध्य प्रदेश देश के उभरते स्टार्टअप राज्यों में शामिल है. मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लागू है, जिसे संशोधित कर स्टार्टअप और उद्यमिता को और बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.

मध्य प्रदेश में निवेश और स्टार्टअप को बढ़ावा

मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कई योजनाएं संचालित हैं. केंद्र की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत 30 जून 2026 तक मध्य प्रदेश के 152 स्टार्टअप को सहायता के लिए चुना गया था और इनके लिए 22.574 करोड़ रुपये की फंडिंग मंजूर की गई थी. स्टार्टअप को फंड ऑफ फंड्स, सीड फंड और क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाओं के जरिए भी सहायता दी जा रही है. सरकार का उद्देश्य नए उद्यमियों को शुरुआती स्तर से लेकर कारोबार बढ़ाने तक जरूरी मदद उपलब्ध कराना है.

नौकरी बाजार में लौटी रफ्तार

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली, 9 सितम्बर. भारत में पिछले माह कार्यालय आधारित नौकरियों में सालाना आधार पर 14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसमें ऑटो, स्वास्थ्य सेवा और रिटेल जैसे सेक्टरों का अहम योगदान रहा. नौकरी.

डॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल नौकरी जाँबस्पीक इंडेक्स पिछले साल अगस्त के 2,664 के मुकाबले बढ़कर 3,028 पर पहुंच गया. यह एक मासिक सूचकांक है, जो देश में व्हाइट-कॉलर नौकरियों के बाजार और भर्ती गतिविधियों की स्थिति को ट्रैक करता है. वाहन क्षेत्र में भी 19 फीसदी बढ़ी जबकि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 16 प्रतिशत और खुदरा क्षेत्र में 15 फीसदी की वृद्धि हुई.

सहारा के निवेशकों को 9267 करोड़ वापस

41.56 लाख लोगों को केंद्र के दखल से फायदा

20 लाख आवेदन अब भी निपटारे के लिए लंबित

नवभारत कनेक्ट
नई दिल्ली, 9 सितम्बर. सहारा समूह की सहकारी समितियों में जमा राशि वापस पाने का इंतजार कर रहे जमाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत सामने आई है. सहकारिता मंत्रालय ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल को फिर से बहाल कर दिया है.

इसके साथ ही सहारा की चार सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के लंबित दावों के सत्यापन और रिफंड की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है. सरकार के अनुसार अब तक 41,56,711 जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े



बैंक खातों में 9,267 करोड़ रुपये सीधे वापस किए जा चुके हैं. रिफंड पोर्टल पर करीब 20 लाख आवेदन अभी भी प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं. पोर्टल की पुनर्बहाली के बाद इन दावों के सत्यापन और पात्र जमाकर्ताओं को राशि लौटाने की प्रक्रिया फिर

शुरू हो गई है. पूरी व्यवस्था को सुरक्षित, पारदर्शी, डिजिटल, कागज-रहित और सत्यापन आधारित बनाया गया है. रिफंड की प्रक्रिया में जमाकर्ता की पहचान, सदस्यता और खाते से जुड़े विवरणों का आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान प्रक्रिया तथा संबंधित समितियों से मिले आंकड़ों के साथ मिलान किया जाता है. सफल सत्यापन के बाद पात्र राशि सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है.

नवंबर 2025 में सहारा की सहकारी समितियों के कामकाज में कई तरह की बाधाएं सामने आई थीं. परिसरों के सील होने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे, जरूरी लाइसेंस, रखरखाव से जुड़े बकाये, मानव संसाधन और प्रशासनिक समस्याओं के कारण रिफंड दावों के सत्यापन और प्रसंस्करण की व्यवस्था प्रभावित हुई थी. सहकारिता मंत्रालय और केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों और अन्य पक्षों के साथ समन्वय किया.

ताइवान और साउथ कोरिया से निकला पैसा

एफआईआई ने भारत में लगाए 2 महीने में 76,795 करोड़ रुपये

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
दिल्ली, 9 सितम्बर. विदेशी निवेशक फिर से भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं. जुलाई और अगस्त में उन्होंने अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों में कुल 76,795 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

इसमें कंप्यूटर सर्विसेज सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिला है और इस सेक्टर में कुल निवेश का एक तिहाई से ज्यादा पैसा लगाया गया है. यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब चिप से जुड़े शेयरों में विदेशी निवेशकों



की खरीदारी कम हो रही है. दक्षिण कोरिया और ताइवान में विदेशी निवेशक सेमीकंडक्टर शेयरों में लगातार बिकवाली कर रहे हैं. इससे उनका पैसा भारत की ओर आने लगा है. भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है. वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जो उम्मीद से बेहतर थी. कंपनियों की पहली तिमाही की कमाई भी उम्मीद से बेहतर रही.

एयरटेल ग्राहकों को 1 साल मुफ्त डुओलिंगो

नवभारत कनेक्ट
नई दिल्ली, 9 सितम्बर. एयरटेल ने अपने 37.6 करोड़ ग्राहकों के लिए डिजिटल सीखने का एक बड़ा अवसर पेश किया है. दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने भाषा सीखने वाले मंच डुओलिंगो के साथ साझेदारी की है.

इसके तहत एयरटेल के मोबाइल, वाई-फाई और डीटीएच ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक साल यानी 12 महीने तक सुपर डुओलिंगो की सदस्यता मिलेगी. ग्राहक एयरटेल ऐप के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और इसके लिए किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी.

सुपर डुओलिंगो के साथ उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन-मुक्त भाषा सीखने का अनुभव मिलेगा. इसमें असीमित ऊर्जा,



कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से वास्तविक समय में बोलने का अभ्यास, उपयोगकर्ता की जरूरत के अनुसार अभ्यास और अपनी गलतियों की समीक्षा जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इन सुविधाओं का उद्देश्य सीखने वालों को केवल पाठ पूरा करने

तक सीमित रखने के बजाय भाषा का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है. डुओलिंगो दुनिया के लोकप्रिय भाषा सीखने वाले मंचों में शामिल है. इसके मोबाइल ऐप पर 40 से अधिक भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं. छोटे-छोटे पाठ, खेल आधारित सीखने की तकनीक, व्यक्तिगत अभ्यास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुविधाओं के जरिए भाषा सीखने की प्रक्रिया को आसान और रोचक बनाया गया है. उपयोगकर्ता यहां शतरंज, गणित और संगीत भी सीख सकते हैं.

डुओलिंगो इंडिया की बिजनेस डेवलपमेंट प्रमुख राशि धनानी के मुताबिक, भारत कंपनी के महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है और छात्रों, पेशवरों तथा तेजी से वैश्विक हो रहे कार्यबल के बीच भाषा सीखने की मांग बढ़ रही है. एयरटेल के साथ साझेदारी से सुपर डुओलिंगो को देशभर के अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.

चीन का निर्यात 25% बढ़ा

बैंकोंक. चीन का निर्यात अगस्त में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़ा. सीमा शुल्क एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि मॉटर वाहन और उच्च प्रौद्योगिकी वाले सामान की मजबूत मांग से निर्यात को बढ़ावा मिला. जुलाई में निर्यात सालाना आधार पर 23.9 प्रतिशत बढ़ा था. अगस्त में आयात भी सालाना आधार पर 28.2% बढ़ा, जबकि जुलाई में इसमें 27.5% की वृद्धि हुई थी. इससे चीन का व्यापार अधिशेष 119.1 अरब डॉलर हो गया जो जुलाई के 112.5 अरब डॉलर के मुकाबले अधिक है. नीति-निर्माताओं ने अमेरिका और अन्य देशों में चीन के लगातार बढ़ते व्यापार अधिशेष को लेकर चिंता जताई है.

एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
भुवनेश्वर, 9 सितंबर. एसओए डीमड यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर साइसेज फैकल्टी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइसेज के छात्रों के लिए बुधवार को ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की गई.

इसमें उन छात्रों को शामिल किया गया जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी. ये छात्र बी.एससी. एग्रीकल्चर 2022-26 बैच औरएम. एससी. (एग्रीकल्चर), (हॉर्टिकल्चर) और 12 अन्य विभागों के 2024-26 बैच के थे. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के



खेती अब सिर्फ एक पारंपरिक विषय नहीं

यह कार्यक्रम उनकी कड़ी मेहनत, लगन, धैर्य, अनुशासन और समर्पण का नतीजा है. प्रोफेसर नंदा ने कहा कि छात्रों ने देश की 15वीं रैंक वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और अब वे बाहर जाकर अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रैंड एंसेसदर बनेंगे. आईएएस के डीन प्रोफेसर संतोष कुमार राउल ने भी इस मौके पर बात करते हुए कहा कि खेती अब सिर्फ एक पारंपरिक विषय नहीं रह गई है.

तौर पर शामिल एसओए के नंदा ने डिग्री पाने वाले छात्रों को वाइस-चांसलर प्रो. प्रदीप कुमार शपथ दिलाई.

समाचार विशेष

चुनाव से पहले भाजपा का ब्राह्मण कार्ड

क्षेत्रीय टीम में 10 चेहरे शामिल
गोरखपुर, 9 सितंबर. चुनावी तैयारियों के बीच भाजपा ने पूर्वांचल में अपनी नई क्षेत्रीय टीम का गठन कर संगठन में सामाजिक समीकरण को साधने का प्रयास किया है.

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की स्वीकृति के बाद घोषित 39 सदस्यीय क्षेत्रीय टीम में सबसे अधिक 10 ब्राह्मण चेहरों को जगह मिली है. चार कायस्थ नेताओं को भी टीम में प्रतिनिधित्व मिला है जबकि पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं. पूर्वांचल की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा की नई क्षेत्रीय टीम में अलग-अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. क्षेत्रीय महामंत्री के चार पदों में से दो पर कायस्थ नेताओं को

जिम्मेदारी मिली है. पिछली टीम के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र सिन्हा को महामंत्री बनाया गया है. पूर्व महानगर अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव को भी महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी रहे डॉ. बच्चा पांडेय को भी महामंत्री बनाया गया है. वहीं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जुड़े भास्कर निषाद को महामंत्री की जिम्मेदारी दी है. कुल मिलाकर नई टीम में अनुभव, संगठनात्मक सक्रियता, सामाजिक प्रतिनिधित्व और नए चेहरों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की गई है. क्षेत्रीय टीम की घोषणा के बाद अब क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी तथा क्षेत्रीय आईटी और सोशल मीडिया टीम की घोषणा होना बाकी है.

कई सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व- क्षेत्रीय टीम में वैश्य, सैथवार, कुशवाहा,

पुराने चेहरों पर भरोसा, युवाओं को भी जगह

नई क्षेत्रीय टीम में संगठनात्मक अनुभव और सक्रियता को भी महत्व दिया गया है. गोरखपुर से आठ कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया है. पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह और पूर्व महानगर अध्यक्ष राशिश गुप्ता को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने पुराने संगठनात्मक अनुभव पर भरोसा जताया है. किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे राधेश्याम पांडेय को मुख्य संगठन में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय बड़े को भी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. इससे संगठन में अनुभवी चेहरों के साथ युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति भी नजर आती है.

बेलदार, कुर्मी, अग्रहरी और भूमिहार समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है. भाजपा के लिए पूर्वांचल में अलग-अलग सामाजिक समूहों का समर्थन चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है.

तमिलनाडु में एडीएमके नेताओं पर विजय की नजर

चेन्नई, 9 सितंबर. तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है. वैसे तो तमिलनाडु में छह विधायकों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन उपचुनाव सिर्फ दो सीटों पर ही होगा.

मुख्यमंत्री सी सोसेफ विजय भी दो सीट से जीते थे और उन्होंने भी एक सीट से इस्तीफा दिया है लेकिन उस सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है. चुनाव आयोग ने जिन दो सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है वो दोनों सीटें अना डीएमके से जीते विधायकों के

इस्तीफे से खाली हुई हैं. दोनों ने सरकार बनाने के लिए विजय का समर्थन किया.

सवाल है कि क्या विजय इस्तीफा देने वाले दोनों विधायकों को टिकट देंगे? जिन दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें एक सीट धर्मपुरम सीट है, जहां से पी सत्यभामा चुनाव जीती थीं. वे उपचुनाव लड़ना चाहती हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि फैसला पार्टी करेगी. दूसरी सीट मदुराथकम है, जहां से माराथम कुमारवेल चुनाव जीते थे.

कार्यकर्ता बनाएंगे रील सीएम योगी करेंगे शेयर

लखनऊ, 9 सितंबर. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं. भाजपा ने अब चुनावी रणनीति को सिर्फ बुथ और घर-घर संपर्क तक सीमित रखने के बजाय सोशल मीडिया को भी संगठन के अभियान से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है.

पार्टी के कार्यकर्ता अब सरकार की योजनाओं और स्थानीय विकास कार्यों की सक्सेस स्टोरी पर रील बनाएंगे, जिन्हें सोशल

मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा. इनमें से चुनिंदा रील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे. यह पूरा अभियान सेवा संकल्प अभियान के तहत चलाया जाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाला यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलाने की तैयारी है. भाजपा इसे 2027 के

विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की जमीनी और डिजिटल ताकत परखने की कवायद के तौर पर देख रही है.

भाजपा के डिजिटल प्लान का सबसे अहम हिस्सा शक्ति केंद्र हैं. रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश के 27 हजार से अधिक शक्ति केंद्रों को कम से कम 10-10 रील तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है. इन रील में किसी सरकारी योजना से लाभ पाने वाले व्यक्ति की कहानी, स्थानीय विकास कार्य या सरकार की उपलब्धि को करीब एक

मिनट के वीडियो में दिखाने की योजना है. वीडियो में लाभार्थी का नाम, स्थान, जिला, योजना और उससे हुए बदलाव जैसी जानकारी शामिल की जाएगी. यानी भाजपा अब योजनाओं का प्रचार सिर्फ नेताओं के भाषण के जरिए नहीं, बल्कि लाभार्थी की जुबानी कहानी के रूप में सोशल मीडिया तक पहुंचाना चाहती है.

जेन-जी पर क्यों है भाजपा की नजर?

भाजपा की इस रणनीति में युवाओं और खासकर जेन-जी को जोड़ने पर विशेष जोर दिखाई देता है. सोशल मीडिया पर छोटे वीडियो और रील युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं. ऐसे में पार्टी पारंपरिक भाषण और पोस्टर से आगे बढ़कर उसी माध्यम में अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाना चाहती है, जहां युवा सबसे ज्यादा समय बिताते हैं. यही वजह है कि सेवा संकल्प अभियान के दौरान रील बनाने की अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है.

जयपुर, 9 सितंबर. राजस्थान में निकाय चुनाव के दौरान टिकट को लेकर उभजे अस्तोषण को धामने के लिए बीजेपी की ओर से चलाया गया मान-मनौव्वल का दौर अब खत्म हो गया है. नाम वापसी की अंतिम तारीख का समय निकलने के साथ ही पार्टी ने बागियों को मनाने की कोशिशों पर विराम लगाते हुए अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

पार्टी स्तर पर उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है, जिन्होंने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में डटे रहने का

फैसला किया है. यानी निकाय चुनाव में बीजेपी ने अब समझाइश की राजनीति से अनुशासन की राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिया है. नाम वापसी तक जिसे मनाने की कोशिश की गई, अब उसके खिलाफ संगठन की कार्रवाई का रास्ता खुल गया है. पार्टी के लिए अगला लक्ष्य बागियों पर फैसला लेने के साथ-साथ अधिकृत प्रत्याशियों को एकजुट संगठन और मजबूत बूथ नेटवर्क के साथ चुनाव मैदान में उतारना होगा.

निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद कई वार्डों में बीजेपी के दावेदारों ने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया था. इसके बाद प्रदेश संगठन ने नाराज नेताओं को मनाने के लिए अंतिम समय तक पूरी ताकत झोंकी. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी ने खुद प्रदेश कार्यालय में बैठकर कई बागियों और मजबूत बूथ नेटवर्क से फोन पर बातचीत की. राजनीतिक स्तर पर समझाइश से

लेकर सामाजिक प्रभाव रखने वाले नेताओं के जरिए भी बागियों को चुनाव मैदान से हटाने की कोशिश की गई. नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही पार्टी के सामने अब तस्वीर साफ हो गई है कि कौन-कौन से नेता संगठन के निर्देश के बावजूद मैदान में बने हुए हैं. ऐसे प्रत्याशियों की सूची तैयार की जा रही है. सूची तैयार होने के बाद संबंधित नेताओं के खिलाफ संगठनात्मक नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. जयपुर संभाग निकाय चुनाव प्रभारी प्रभुलाल सैनी ने कहा कि पार्टी ने अधिकांश नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया है और बागियों की संख्या बहुत कम है.

